

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-प्रदीप सिंह सागावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - डिक्री 116/2022

पंजीयन दिनांक- 3.8.2022

1. रतन पिता चतरभुज गाडरी निवासी-बानसेन तहसील भदेसर जिला-चित्तौड़गढ़ ।  
-अपीलांत

विरुद्ध

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर तहसील भदेसर जिला-चित्तौड़गढ़।
2. सरकार जरिये जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ ।

रेस्पोंडेन्टगण



अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भदेसर प्रकरण संख्या 199/2021 निर्णय व डिक्री दिनांक 20.7.2022

- उपस्थित-
1. सावन श्रीमाली -अधिवक्ता अपीलांत
  2. पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट सं.1,2

निर्णय

दिनांक:- 27.12.2023

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है वादी/अपीलांत ने एक वाद अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88-188 के तहत मौजा बानसेन, तहसील भदेसर में वादी अपीलांत के कब्जे स्वामित्व आधिपत्य की कृषि आराजियात जिसके खाता संख्या 01 की आराजी नम्बर 500 रकबा 0.38 हैक्टेयर के संबंध में प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.7.2022 को वादी अपीलांत का वाद अस्वीकार किया गया जिसके विरुद्ध अपील अपीलांत वादी इस न्यायालय में पेश हुई।

इस न्यायालय में अपीलांत वादी की ओर से अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस जारी किये गये एवं सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोंडेन्ट प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली जरिये पत्रांक तलब की गई व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।


*(Handwritten Signature)*

सम्मान अपील प्राधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधिवक्ता अपीलांत वादी ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजियात ग्राम बानसेन के खाता संख्या 01 की आराजी नम्बर 500 रकबा 0.38 हैक्टेयर में से 0.20 हैक्टेयर कृषि आराजियात अपीलांत वादी के आधिपत्य उपयोग उपभोग व कब्जे काशत में बाप दादाओ के समय से चली आ रही है उक्त कृषि आराजियात का राज्य सरकार में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-91 के तहत की जा रही कार्यवाही में वार्षिक लगान का 50 गुणा शारित राशि जमा कराता चला आ रहा है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलांत वादी को सुनवाई का समूचित अवसर दिये बिना ही निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो कानूनी प्रावधानों के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। अंत में उन्होंने अपील अपीलांत स्वीकार करने का अनुरोध किया।




विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोजेन्टगण प्रतिवादीगण ने वक्त बहस निवेदन किया कि विवादित कृषि आराजियात बिलानाम सरकार दर्ज होकर सरकारी आराजियात है। अपीलांत वादी ने सरकारी आराजियात आराजी नम्बर 500 रकबा 0.38 हैक्टर में से 0.20 हैक्टर आराजियात के सम्बन्ध में घोषणा का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वादपत्र के साथ नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस व नकल नोटिस जो उपतहसीलदार भादसौडा के द्वारा वर्ष 2018, 2019 व 2020 में अपीलांत वादी के द्वारा उक्त कृषि आराजियात पर अनाधिकृत कब्जा कर लेने से अतिक्रमण के सम्बन्ध में जारी किया गया व अपीलांत वादी पर शारित भी आरोपित की गई। अपीलांत वादी का अतिक्रमण किसी भी स्थिति में नियमन योग्य नहीं है व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में रेस्पोजेंट संख्या 1 की ओर से जो रिपोर्ट दिनांक 03.03.2022 प्रस्तुत की गई है उसमें भी उक्त आराजियात पर अपीलांत वादी का नियमन योग्य कब्जा नहीं मानते हुए अतिक्रमी माना है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोजेंटगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध बिना तामिल के दिनांक 28.03.2022 को निर्णय एवं डिक्री पारित की गई जिस पर रेस्पोजेंट संख्या 1 प्रतिवादी की ओर से दिनांक 20.07.2022 को आपति प्रस्तुत की गई। उक्त आपति को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने स्वीकार कर अपीलांत वादी का वादपत्र प्रमाणित नहीं होना मानते हुए अपीलांत वादी को अतिक्रमी मानते हुए वादपत्र निरस्त किया गया जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत निर्णय व डिक्री है जिसके विरुद्ध अपीलार्थी वादी की ओर से प्रस्तुत अपील विधिविरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

  
 राजस्थान आपील प्राधिकारी  
 चित्तौड़गढ़ (राज.)

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व उक्त पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में रेस्पोंडेंट संख्या 1 प्रतिवादी की ओर से मौका रिपोर्ट दिनांक 03.03.2022 प्रस्तुत की गई है जिसमें आराजी नम्बर 500 रकबा 0.38 हैक्टर बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड है व उक्त आराजियात में से 0.20 हैक्टर भूमि में से अपीलांत वादी का अतिक्रमण बताया गया है। अपीलांत वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी, नकल लगान की रसीदे व अतिक्रमण के नोटिस का अवलोकन करने से अपीलांत वादी का नियमन योग्य अतिक्रमण नहीं होकर आकस्मिक अतिक्रमण है जिसके आधार पर अपीलांत वादी घोषणा कराये जाने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 28.03.2022 को रेस्पोंडेंट प्रतिवादीगण के विरुद्ध बिना तामिल व बिना सुनवाई के अपीलांत वादी का वादपत्र डिक्री किया था जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत आपत्ति आवेदन को स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2022 को निरस्त किये जाने की जो निर्णय व डिक्री पारित की है वह विधिसंगत होने से अपीलांत वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार होने योग्य नहीं है।

फलस्वरूप अपील अपीलांत वादी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर का प्रकरण संख्या 199/2021 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.7.2022 यथावत रखी जाती है। डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को खूले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्य प्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावें।

  
(प्रदीप सिंह)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी  
चित्तौड़गढ़

## अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जापा दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- प्रदीप सिंह सांगावत, (आर.ए.एस)

अपील सं.:- 116/2022/डिक्री

1. रतन पिता चतरभुज गाडरी निवासी-बानसेन तहसील भदेसर जिला-चित्तौड़गढ़ ।  
-अपीलांत

विरुद्ध


1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर तहसील भदेसर जिला-चित्तौड़गढ़ ।
2. सरकार जरिये जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ ।

रेस्पोजेन्टगण

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर प्रकरण संख्या 199/21 निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2022 वाद पत्र बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : अपील अपीलांत वादी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर का प्रकरण संख्या 199/2021 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.7.2022 यथावत रखी जाती है ।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि 0 रुपये है,..... द्वारा दिये जाने हैं। मूल वाद के खर्चे ..... द्वारा दिये जाने हैं । यह आज दिनांक 27.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।



  
(प्रदीप सिंह सांगावत)  
राजस्थान अपील प्राधिकारी,  
चित्तौड़गढ़